

भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 377

दिनांक 04 फरवरी, 2025

जलवायु अनुकूल फसल किस्में

377. श्री बैन्नी बेहनन:

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार केरल की कृषि-जलवायु स्थितियों के अनुकूल जलवायु-सह फसल किस्मों के विकास को प्रोत्साहित कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) जल और कृषि चुनौतियों के लिए समग्र दृष्टिकोण सुनिश्चित करने हेतु विभागों में जल प्रबंधन नीतियों को एकीकृत करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और
- (ग) क्या सरकार ने कृषि पर चरम मौसमी घटनाओं के प्रभाव को कम करने के लिए केरल में पर्याप्त निगरानी और पूर्व-चेतावनी प्रणाली स्थापित की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री
(श्री भागीरथ चौधरी)

(क): भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तत्वावधान में भाकृअनुप संस्थानों तथा राज्य/केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालयों सहित राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली (एनएआरएस) ने वर्ष 2014-2024 के दौरान विभिन्न फसलों की 2900 किस्में विकसित की हैं, जिसमें से 2661 किस्में जलवायु-अनुकूल हैं। इस अवधि के दौरान केरल राज्य के लिए 63 खेत फसल किस्में विकसित की जा चुकी हैं, जिसमें खाद्यान्न की 23, तिलहन की 2, दलहन की 10, चारा फसलों की 15 और गन्ने की 13 किस्में हैं। इसमें से 58 किस्में जलवायु-अनुकूल हैं।

(ख): भारत सरकार की प्रति बूंद अधिक फसल (पीडीएमसी) नामक केन्द्र प्रायोजित योजना वर्ष 2015-16 से लागू की जा चुकी है। यह योजना टपक (ड्रिप) एवं छिड़काव (स्प्रिंकलर) सिंचाई प्रणालियों जैसी सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली के माध्यम से खेत स्तर पर पानी के दक्षतापूर्वक उपयोग को बढ़ाने पर केन्द्रित है। प्रति बूंद अधिक फसल (पीडीएमसी) का कार्यान्वयन प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के एक घटक के रूप में वर्ष 2015-16 से 2021-22 के दौरान और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) के अंतर्गत वर्ष 2022-23 के आगे कार्यान्वित की गई थी। इस योजना के विभिन्न घटक पानी को बचाने के साथ-साथ फर्टिगेशन के माध्यम से उर्वरक के उपयोग, श्रम व्यय, अन्य इनपुट लागतों में कमी लाते हैं और किसानों की आय को समग्र रूप से बढ़ाते हैं। सरकार पीडीएमसी के अंतर्गत टपक एवं छिड़काव सिंचाई प्रणालियों को स्थापित करने के लिए लघु एवं सीमान्त कृषकों को 55 प्रतिशत की दर से तथा अन्य कृषकों को 45 प्रतिशत की दर से वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

(ग): फसल की बरबादी और मौसम की चरम स्थितियों के कारण होने वाले नुकसान को कम करने के साथ-साथ मौसम की उदार स्थितियों का फायदा उठाने के लिए दिन-प्रतिदिन के कृषि कार्यों पर निर्णय लेने में किसानों की सहायता के लिए भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ग्रामीण कृषि मौसम सेवा (जीकेएमएस) नामक एक योजना संचालित कर रहा है। इसकी सहायता से कृषक समुदाय के लाभ के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों और अन्य संस्थानों के सहयोग से मौसम के पूर्वानुमान आधारित कार्यात्मक कृषि मौसम परामर्श सेवाएं दी जाती हैं। इस योजना के अंतर्गत देश भर में वर्तमान में 130 एगोमेट फील्ड इकाईयां कार्यरत हैं, जो राज्य कृषि विश्वविद्यालयों, भाकृअनुप के संस्थानों तथा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आदि में स्थित हैं। आईएमडी के क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केन्द्रों (आरएमसी) और मौसम केन्द्रों (एनसी) द्वारा पाक्षिक बुलेटिनों के साथ-साथ किसानों को मौसम के दैनिक पूर्वानुमान और तात्कालिक पूर्वानुमान (नॉउकास्ट) की जानकारी का भी प्रसार किया जाता है। 130 एएमएफयू में से अम्बलावायल, पिल्लीकोड, त्रिशूर, वेल्लायानी और कुमारकोम नामक 5 एएमएफयू केरल के सभी महत्वपूर्ण कृषि जिलों के लिए एएस बुलेटिनों की जिला स्तर पर तैयारी कर रहे हैं। ये इकाईयां मल्टी चैनल विस्तार प्रणालियों जैसे प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, दूरदर्शन, रेडियो, इंटरनेट आदि जैसे माध्यमों से एएस के विस्तार में भी संलग्न हैं। इसमें किसान पोर्टल के माध्यम से मोबाइल फोनों की सहायता से एसएमएस और सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड के अंतर्गत निजी कंपनियों के माध्यम से भी संदेश भेजा जाना शामिल है। चक्रवात, गहरे दबाव (डीप डिप्रेशन) आदि जैसी मौसम की चरम स्थितियों के दौरान किसान पोर्टल के माध्यम से एसएमएस आधारित सतर्कता और चेतावनी की सूचनाएं भी उचित उपचारात्मक उपायों के साथ भेजी जाती हैं।

भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए 'मेघदूत' और 'मौसम' नामक मोबाइल ऐप के माध्यम से किसान अपने जिलों से संबंधित चेतावनियों और कृषि मौसम संबंधी परामर्श की जानकारी प्राप्त करते हैं। कृषि कार्यों पर समुचित निर्णय लेने के लिए किसानों को वास्तविक समय में मौसम की अद्यतन जानकारी देने के लिए एएमएफयू भी 'व्हाट्स-ऐप', 'फेसबुक', यूट्यूब आदि जैसे सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। केरल में ये सेवाएं कृषि सूचना प्रबंधन प्रणाली (एआईएमएस), कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, केरल सरकार के साथ एकीकृत कर दी गई हैं। इस प्लेटफॉर्म की सहायता से लगभग 40 लाख किसानों को अंग्रेजी एवं क्षेत्रीय भाषा में सूचना प्राप्त हो रही है।

हाल ही में, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (MoES) ने पंचायती राज मंत्रालय (MoPR) के साथ सहयोग करके 24 अक्टूबर 2024 को भारत की लगभग सभी ग्राम पंचायतों के लिए पंचायत स्तरीय मौसम पूर्वानुमान आरंभ किए हैं। ये पूर्वानुमान डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे-ई-ग्रामस्वराज (<https://egramswaraj.gov.in>), मेरी पंचायत ऐप, MoPR का ई-मानचित्र और IMD, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का मौसमग्राम से प्राप्त किए जा सकते हैं।

सूखे की मॉनिटरिंग के लिए कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (DA&FW) ने स्पेस ऐप्लीकेशन सेंटर (SAC), ISRO के सहयोग से एक जिओपोर्टल विकसित किया है। इस जियोपोर्टल पर वर्षा, मृदा नमी, सुदूर संवेदन आधारित फसल स्थिति, जल भंडारण आदि से संबंधित बहु-सूखा सूचकांकों का डेटा उपलब्ध होता है। यह पोर्टल एक सिंगल विंडो डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो सूखा सूचकांक उपलब्ध करवाता है तथा जिला और तहसील स्तर पर सूखे की स्थिति का आसान, उचित समय पर एवं उद्देश्यपरक मूल्यांकन की दिशा में विभिन्न हितधारकों को समर्थ बनाता है। यह पोर्टल संभावित सूखा स्थितियों की पहचान करने में भी सहायता करता है जिससे प्रभावी सूखे की प्रबंधन कार्यनीति के सहयोग से समय पर उपाय करने के लिए मदद मिलती है।
